राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 2 अंक 324

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, गुरुवार, 2 मई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

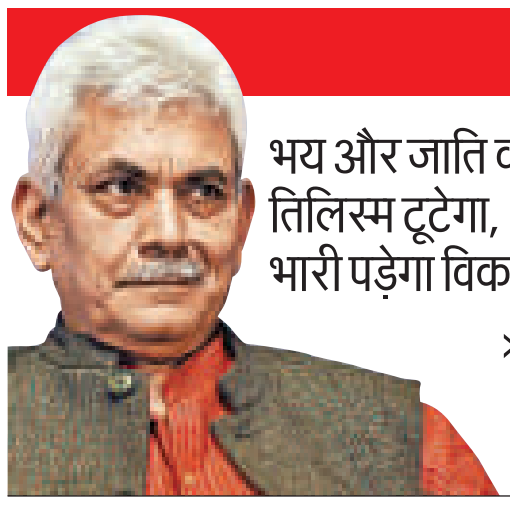

भय और जाति का तिलिस्म टूटेगा, भारी पड़ेगा विकास

>>6

दैनिक जागरण
हिंदी बेस्टसेलर
● कथा ● कथेतर
● अनुवाद ● कविता

दैनिक जागरण हिंदी बेस्ट सेलर (जनवरी–मार्च 2019) कथेतर सूची पेज 10

महासमर 2019

- अलवर में सबका साथी है 'राजा', सामने है 'मोदी का महंत' ● पेज 4
- मजबूत भारत के लिए गठबंधन और कांग्रेस की सच्चाई जानना जरूरी : मोदी ● पेज 5
- भाजपा के वोट काटने के लिए खड़े हैं कांग्रेस के उम्मीदवार : प्रियंका ● पेज 5
- देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहियों पर घूमती उप्र की सियासत ● पेज 6

विश्वास News

खली के बसपा में शामिल होने की पोस्ट फर्जी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 6

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल के संपर्क में था दीपक तलवार

नई दिल्ली : ईडी ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि दीपक तलवार तत्कालीन उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के संपर्क में था। उसने बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए विदेशी विमानन कंपनियों को फायदा पहुंचाया। कोर्ट ने इस मामले में दीपक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 11

अप्रैल में 1.13 लाख करोड़ रुपये हुआ जीएसटी संग्रह

नई दिल्ली : टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाये गये कदमों से जीएसटी संग्रह रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस साल अप्रैल में 1.13 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह हुआ जो गत वर्ष के मुकाबले 10 फीसद अधिक है। एक जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी संग्रह का यह आंकड़ा अब तक का सर्वोच्च है।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 12

अपूर्वी चंदेला विश्व की नंबर एक निशानेबाज बनीं

नई दिल्ली : भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने बुधवार को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि हमवतन अंजुम मोदगिल हाल के वर्षों में किए प्रदर्शन के बूते दूसरे स्थान पर पहुंच गईं। अपूर्वा उन पांच भारतीय निशानेबाजों में हैं जिन्होंने 2020 के ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। जयपुर निवासी चंदेला ने फरवरी में आइएसएसएफ विश्व कप में 252.9 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता था।

सनराइजर्स
मुंबई इंडियंस
vs
सनराइजर्स हैदराबाद
रात 8:00 बजे से
स्थान : मुंबई
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

जैश सरगना मसूद अजहर अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित

बड़ी जीत ▶ चीन ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ, वीटो लिया वापस, पाक के बदले बोल, कहा– पूरी तरह से लागू करेंगे यूएन का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत, कहा– आतंकवाद मिटाने के लिए अहम कदम

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

संसद, पठानकोट और पुलवामा जैसे हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। पिछले एक दशक से अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंध घोषित करवाने में जुटे भारत की कूटनीतिक कोशिशों को बुधवार को सफलता तब मिली जब चीन ने अपना वीटो हटाकर इसका समर्थन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की बड़ी जीत बताते हुए कहा, इससे आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कोशिशों में मदद मिलेगी। इस फैसले से पाकिस्तान के बोल भी बदल गए हैं। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, वह अजहर के बारे में संयुक्त राष्ट्र के फैसले को तुरंत लागू करेगा।

बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने जानकारी दी, 'मसूद अजहर यूएन की तरफ से आतंकी घोषित हो गया है। इसमें सभी बड़े-छोटे देशों ने मदद की है। उन सभी देशों को मदद के लिए धन्यवाद।' दरअसल, अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विशेष समिति बना रखी है, जिसे 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति के तहत घोषित आतंकियों को किसी भी देश में शरण देना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि उसके लिए फंड जुटाना भी मुश्किल होता है। उस व्यक्ति और उससे जुड़े हर तरह के संगठन की कड़ी निगरानी की जाती है और उनके बारे में संयुक्त राष्ट्र के तमाम देशों के साथ सूचनाएं भी साझा करनी पड़ती हैं। लिहाजा अब मसूद अजहर के नाम से जुड़े हर बैंक खाते और संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा।

'अजहर का मुद्दा अभी शुरुआत': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर शाम जयपुर की रैली में अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर संतोष जताया। इसे आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की भारत की कोशिशों का नतीजा बताते हुए कहा, 'अजहर का मुद्दा अभी शुरुआत है। देखते रहिए आगे क्या क्या होता है।' भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मोदी के कूटनीतिक प्रयासों से ही यह सफलता मिली है। इसीलिए भारत को मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पुलवामा हमले समेत भारत की धरती पर कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले मसूद अजहर और उसके संगठन को उनके किए अपराधों और गुनाहों की सजा दिलाने में संयुक्त राष्ट्र का यह कदम काफी मददगार सिद्ध होगा।

चीन ने कहा, नए सिरे से अध्ययन में नहीं दिखी कोई आपत्ति : संयुक्त राष्ट्र में भारत की कोशिशें इसलिए सफल रहीं क्योंकि चीन ने मार्च, 2019 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ तकनीकी रोक (वीटो) वापस ले ली। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में पेश संशोधित प्रस्तावों के नए सिरे से अध्ययन के बाद तकनीकी रोक हटाई गई है। चीन ने पाक का जिक्र करते हुए कहा, वह आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है और उसके योगदान को स्वीकारा जाना चाहिए। प्रस्ताव लाने वाले देश फ्रांस ने भी चीन के रुख का स्वागत किया है।

पाक बोला, पुलवामा हमले से नहीं जोड़ा गया : पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूएन में पेश संशोधित प्रस्ताव में मसूद अजहर को किसी सियासी मुद्दे और पुलवामा हमले से नहीं जोड़ा गया है। प्रस्ताव में कश्मीर का जिक्र भी नहीं है। हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि भारत का मुख्य उद्देश्य अजहर पर प्रतिबंध लगाने का था और वह हो गया है।

सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों का मिला समर्थन : भारत की यह कूटनीतिक जीत सिर्फ चीन के मिजाज में बदलाव लाने के हिसाब से ही अहम नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों का सहयोग हासिल किया है। यह सरकार की कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है। वर्ष 2009 में पहली बार भारत ने अजहर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद चार बार ऐसा प्रस्ताव पेश हो चुका है और हर बार चीन उस पर वीटो लगाकर खारिज करवाता रहा है।

लंबे वक्त से चल रही थी तैयारी

- पुलवामा हमले के बाद भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से की बात
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हर सदस्य से किया गया संपर्क
- हर देश को भारत ने जैश और अजहर की आतंकी करतूतों के दिए सुबूत
- विदेश सचिव ने हालिया चीन यात्रा में जैश की भूमिका के फिर सौंपे सुबूत
- अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, उसके बगैर भी किसी दूसरे तरीके से प्रतिबंध लागू करने की तैयारी

भाजपा के 'मोदी है तो मुमकिन है' नारे को मिलेगी नई धार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत में कई आतंकी घटनाओं के सूत्रधार रहे आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी ने भारत और भारत सरकार की ताकत को तो सिद्ध कर ही दिया है, इसके चुनावी असर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने इसके सहारे 'मोदी है तो मुमकिन है' के चुनावी नारे को धार दे दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद बालाकोट का सबूत मांग रहे विपक्षी दलों को कठघरे में खड़ा करते हुए यह पूछा जाएगा कि जब अंतरराष्ट्रीय ताकतें भारत की ताकत को महसूस कर रही हैं तो फिर घर के अंदर सवाल खड़ा क्यों किया जा रहा है। परोक्ष रूप से इसे चीन पर जीत का भी संदेश बनाया जाएगा।

पिछले दो साल में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के जरिये पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन दूसरा पड़ोसी चीन हमेशा से भारत पर हावी रहा। हाल के दिनों में आपसी रिश्तों और कूटनीतिक पहल के जरिये पहली बार चीन को भी भारत की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अजहर मसूद पर पाबंदी के लिए चीन का राजी होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह भी माना जा रहा है कि इस जीत को भाजपा बहुमत वाली मजबूत सरकार के तर्क का आधार बनाएगी। गौरतलब है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कहते रहे हैं कि विश्व में भारत की धमक इसलिए है क्योंकि यहां मजबूत सरकार है, कोई मजबूर सरकार नहीं। हाल की चुनावी रैलियों में वह आतंक को देश का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताते रहे हैं। ऐसे में जब आतंक का सरगना और भारत का बड़ा दुश्मन घिर गया है तो चुनाव में इसका असर होना तय माना जा रहा है।

- बालाकोट पर सुबूत मांगने वाले विपक्ष को कठघरे में खड़ा करेगी भाजपा
- फैसले को मजबूत बहुमत वाली सरकार के लिए आधार बना सकती है पार्टी

आतंक पर अंकुश

मसूद का अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित होना पाक के लिए बड़ी चेतावनी पेज>>7

जानिए जैश सरगना मसूद अजहर पर लगे प्रतिबंध के मायने पेज>>7

गढ़चिरौली में नक्सलियों ने किया आइईडी धमाका, 15 जवान शहीद

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित कार्रवाई टीम के सदस्य थे सभी जवान
- 22 अप्रैल 2018 में इसी यूनिट ने 40 प्रमुख नक्सलियों को मारा था

महाराष्ट्र दिवस पर बुधवार को राज्य के गढ़चिरौली जिले के जाम्बुरगढ़ क्षेत्र में नक्सलियों के एक बड़े हमले में पुलिस की विशेष कमांडो फोर्स के 15 जवान शहीद हो गए। विशेषकर नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के लिए बनाई गई क्विक रेस्पांस टीम (क्यूआरटी) के ये जवान एक निजी वाहन से जा रहे थे, जिसे आइईडी विस्फोट से उड़ा दिया गया। हमले में वाहन चालक भी मारा गया है। एक दिन पूर्व ही नक्सलियों ने इसी क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगे 36 वाहन फूंक दिए थे। गढ़चिरौली में 20 दिन में यह दूसरा हमला है।

महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब एक बजे नक्सलियों ने गढ़चिरौली जिले में कुरखेड़ा से छह किलोमीटर दूर लैंडमाइन विस्फोट किया। इस स्थान से कुछ दूर पर ही 22 अप्रैल 2018 को इसी कमांडो यूनिट ने एक ऑपरेशन में 40 प्रमुख नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सली हफ्ते भर से मारे गए अपने इन्हीं साथियों की बरसी मना रहे थे। खुफिया सूत्रों ने सूचना दी थी कि इस दौरान नक्सली किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं।

जवानों को फंसाने के लिए जलाए थे 36 वाहन : पुलिस को जाल में फंसाने के लिए ही नक्सलियों ने मंगलवार को इसी क्षेत्र में कुरखेड़ा-कोरची मार्ग के निर्माण में लगे 36 वाहन जला दिए थे। इसके बाद ही बुधवार को कमांडो यूनिट निजी वाहन से उस क्षेत्र में जा रही थी। हमले के बाद राजभवन में आयोजित महाराष्ट्र दिवस समारोह रद कर दिया गया।

20 दिन पहले भी किया था हमला : 20 दिन पहले ही विदर्भ क्षेत्र में मतदान से एक दिन पहले नक्सली हमले में सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया था। यह हमला गढ़चिरौली स्थित इटापल्ली के गट्टा क्षेत्र में हुआ था। उससे एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में एक भाजपा विधायक की मृत्यु हो गई थी।

मैं सभी बहादुर सुरक्षाकर्मियों को सलाम करता हूं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरे विचार व एकजुटता शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ऐसी हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गढ़चिरौली में बुधवार को आइईडी धमाके में जवानों के वाहन के परखचे उड़ गए। प्रेट्र

स्थानीय लोगों के विरोध से नाराज थे नक्सली

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कोचिनारा, बुटेकासा एवं सातपुती क्षेत्रों में नक्सलियों ने मतदान बहिष्कार के बैनर-पोस्टर लगाए थे। जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने जला दिया था। तभी से माना जा रहा था कि नक्सली इसकी प्रतिक्रिया में बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन क्षेत्र में मतदान न सिर्फ शांतिपूर्ण निपटा, बल्कि पहले की तुलना में मत प्रतिशत भी बढ़ा है। बता दें कि गढ़चिरौली जिले की सीमाएं नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से मिली हुई हैं। इसलिए यह त्रिकोण नक्सलियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है।

ग्रामीणों ने तोड़ दिया था नक्सलियों का स्मारक

पिछले दिनों ही 'दैनिक जागरण' से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने दावा किया था कि सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं सुरक्षाबलों की सख्ती के कारण 11 राज्यों के 90 जिलों में फैला नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। गढ़चिरौली के संदर्भ में अहीर का यह दावा इसलिए भी सही साबित होता दिख रहा था क्योंकि करीब साल भर पहले गढ़चिरौली के भामरागढ़ तालुका में ग्रामीणों ने मारे गए नक्सली कमांडरों की याद में नक्सलियों द्वारा बनाया गया एक स्मारक गुड़ी पड़वा के दिन तोड़ डाला था, लेकिन गढ़चिरौली में हुए इस हमले ने सुरक्षाबलों की चिंता बढ़ा दी है।

नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी पेज>>3

एकतरफा प्यार में महिला डॉक्टर की हत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में महिला डॉक्टर गरिमा मिश्रा की उन्हीं के परिचित डॉक्टर चंद्रप्रकाश वर्मा ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों एक ही मकान में तीसरी मंजिल पर किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। बताया जाता है कि चंद्र प्रकाश गरिमा से एकतरफा प्यार करता था, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर रही थीं। इसी खुन्नस में उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

एडिशनल डीसीपी अमित शर्मा के मुताबिक, मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली डॉ. गरिमा मिश्रा (25) करोलबाग स्थित दिल्ली सरकार के जोशी अस्पताल में नौकरी करती थीं। दो माह पहले नौकरी छोड़कर एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) की तैयारी करने लगीं। रंजीत नगर की गली नंबर 2 में किराए पर रहने वाली गरिमा के बगल वाले कमरे में डॉ. चंद्रप्रकाश साथी डॉ. राकेश के साथ रहता था।

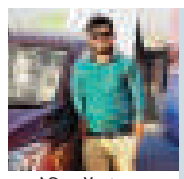

आरोपित डॉ. चंद्रप्रकाश

चाकू से गला रेतने के बाद फरार हुआ आरोपित, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तलाश

चंद्र प्रकाश भी एमडी की तैयारी कर रहा था, जबकि डॉ. राकेश सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल में नौकरी करते हैं। मंगलवार शाम डॉ. राकेश कहीं गए हुए थे। शक है कि उसी दौरान चंद्रप्रकाश गरिमा के कमरे में घुस गया। अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद रसोई के चाकू से गरिमा का गला रेत दिया। इसके बाद कमरे का बाहर से ताला बंद कर अपने कमरे में आ गया। शाम 8.30 बजे डॉ. राकेश घर आए, तो देखा कि चंद्रप्रकाश घबराया हुआ है और किताबें जमा कर रहा है। पूछने पर कहा, दोस्त को किताबें देने जा रहा है, लेकिन वापस नहीं लौटा। गरिमा को मंगलवार देर शाम आठ बजे गुरुग्राम में काम करने वाले ममेरे भाई के साथ गोरखपुर जाना था। मंगलवार शाम वह कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पहुंचे और गरिमा को कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। इस पर वह रात 10:30 बजे रंजीत नगर पहुंचे। गरिमा के कमरे में बाहर से ताला लगा देखकर उन्होंने बगल के कमरे में मौजूद डॉ. राकेश से पूछा तो उन्होंने गरिमा के बारे में जानकारी होने से इन्कार किया। इस पर उन्होंने स्टूल पर चढ़कर दरवाजे के ऊपर रोशनदान से झांककर देखा तो कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन पंखे चल रहे थे।

मोबाइल फोन की लाइट जलाकर नीचे की तरफ देखा तो गरिमा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी दिखी। उन्होंने डॉ. राकेश की मदद से दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर पहुंचे, जहां गरिमा मृत पड़ी थी। जानकारी मिलने पर मकान मालिक ने रात करीब 11.15 बजे पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लेडी हार्डिंग अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बेंगलुरु से परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर बुधवार को शव परिजनों को सौंप दिया। (पेज-2 भी देखें)

साध्वी प्रज्ञा के चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे की पाबंदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चुनाव प्रचार के दौरान विद्वेष फैलाने वाले भाषणों के चलते निर्वाचन आयोग ने भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी है। आयोग ने आदेश में साध्वी प्रज्ञा के बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर दिए बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भविष्य में ऐसे बयानों से बचने की नसीहत भी दी है।

आयोग ने साध्वी के बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल होने वाले बयान पर संज्ञान लेते हुए कहा कि वह उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनका बयान भड़काऊ और धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वाला है। वह याद रखें कि चुनाव में धार्मिक व जातिगत आधार पर वोट नहीं मांग सकती हैं। उनके बयानों से सीधे तौर पर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है।

चुनाव आयोग ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर दिए बयान के चलते की कारवाई

चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा के भोपाल में चुनाव प्रचार के दौरान शहीद अफसर हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर भी नाराजगी जाहिर की है। साध्वी को फटकार लगाते हुए आयोग ने याद दिलाया है कि देश में इस वक्त आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। हालांकि आयोग इस बात से अवगत है कि साध्वी ने अपना बयान वापस ले लिया है और इस पर माफी भी मांगी है। आयोग ने साध्वी से कहा है कि उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में जाति निरपेक्ष हो कानून

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कानून जाति निरपेक्ष और एकसमान होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए बुधवार को यह टिप्पणी की। केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट के 20 मार्च 2018 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। उस फैसले में कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को नरम कर दिया है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, 'देश में कानून एकसमान होना चाहिए। यह सामान्य श्रेणी या एससी/एसटी श्रेणी का नहीं होना चाहिए।' केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह अपना फैसला सुरक्षित रख रही है। अटार्नी जनरल ने शुरू में कहा कि मार्च में दिया गया फैसला समस्या पैदा करने वाला है और कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आम्रपाली समूह ने होम बायर्स से धोखाधड़ी कर प्रथम श्रेणी का अपराध किया है, अदालत ने धांधलियों की अनदेखी के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथारिटी और बैंकों को भी लताड़ा

अफसोस! भ्रष्टाचार के लिए मृत्युदंड नहीं दे सकते

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस कंपनी ने होम बायर्स से धोखाधड़ी करके प्रथम श्रेणी का अपराध किया है। देश भर में लाखों लोगों के आम्रपाली समेत कई बिल्डरों की धांधली का शिकार होने पर खिन्नता जाहिर करते हुए सर्वोच्च अदालत ने अपनी बेबसी जताते हुए कहा, 'हम भ्रष्टाचार के लिए मृत्युदंड नहीं दे सकते।'

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पूरे भारत में बिल्डरों ने प्रशासन और बैंकों की शह पर मानकों का उल्लंघन करके गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर ली हैं। अदालत ने आम्रपाली समूह समेत तमाम बिल्डरों की धांधलियों को अनदेखा करने के लिए नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथारिटी और बैंकों को लताड़ा।

जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की खंडपीठ ने आम्रपाली समूह के विभिन्न प्रोजेक्टों में करीब 42,000 फ्लैटों के कब्जे का बरसों से इंतजार कर रहे फ्लैट खरीददारों की याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई की। इस दौरान खंडपीठ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अथारिटी से कहा कि समय रहते उनकी कार्रवाई से कुछ प्रोजेक्ट को बचाया जा सकता था। खंडपीठ ने कहा, 'हम जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है और बिल्डरों की मिलीभगत से किस तरह से इन अफसरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। नियमों का भयावह तरीके से उल्लंघन किया गया है। जनता और उसके विश्वास को बड़े पैमाने पर छला गया है।' खंडपीठ ने अपने क्षोभ के साथ ही निराशा जताते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी केवल भारत में हो सकती है, लेकिन हम भ्रष्टाचार के लिए सजा-ए-मौत नहीं दे सकते हैं।'

इससे पहले, नोएडा अथारिटी ने जब अदालत को बताया कि वह बिल्डरों और डेवलेपरों की अनियमितताओं पर नजर रखते हैं तो जजों ने जमकर फटकार लगाई। नोएडा की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा, 'जब कोई बिल्डर अथारिटी से लीज पर मिली जमीन को लेकर कोई धांधली करते हैं तो हमें पता चल जाता है। हम (नोएडा) पहले कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं। और अगर धांधली फिर भी जारी रहती है तो वह बिल्डर की लीज रद कर देते हैं।'

इस पर खंडपीठ ने वकीलों से पूछा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धांधली करने वाले कितने बिल्डरों के खिलाफ आपने उनकी लीज रद की है। अदालत ने कहा, 'नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पूरी पट्टी को देखिये। यह इंदौर, भोपाल और अन्य शहरों में भी हो रहा है। बैंकों और प्राधिकरण के साथ मिलकर मानकों का उल्लंघन करते हुए गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं। यह इमारतें कम्प्लीशन सर्टीफिकेट न मिलने के चलते बेची नहीं जाती हैं।' वकील ने कहा कि उन्हें इस बारे में अथारिटी से जानकारी लेनी होगी लेकिन ऐसे मामलों में लीज रद होने की घटनाएं दुर्लभ होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले दस सालों में आपने कुछ नहीं किया। मानकों का उल्लंघन होने पर या डिफाल्टर होने पर आप मामले से मुंह मोड़ लेते हैं। बिल्डरों के आपको पैसा नहीं देने के बावजूद नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथारिटी कुछ नहीं करती। दरअसल आप सब बिल्डरों से मिले हुए हैं और बड़े पैमाने पर जनता से धोखाधड़ी कर रहे हैं।

होम बायर्स की ओर से पेश वकील कृष्णन वेणुगोपाल ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने बिल्डरों को लीज पर जमीन केवल कुल कीमत की दस फीसद पर ही दे दी जाती है। बाकी की धनराशि इंस्टॉलमेंट में दी जाती है।

टिप्पणी

- पूरे भारत में बिल्डरों ने प्रशासन और बैंकों की शह पर मानकों का उल्लंघन करके गगनचुंबी इमारतें खड़ी कीं
- आम्रपाली समूह के 42,000 फ्लैटों के कब्जे का बरसों से इंतजार कर रहे फ्लैट खरीददारों की याचिकाओं पर सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई जांच कमेटी के समक्ष पेश हुए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शिकायतकर्ता महिला ने कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार किया था
- मामले में आगे एकतरफा सुनवाई जारी रखेगी कमेटी

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई बुधवार को उन पर लगे आरोपों की जांच कर रही तीन सदस्यीय आंतरिक जांच कमेटी के समक्ष पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने मुख्य न्यायाधीश पर अमर्यादित आचरण के आरोप लगाए हैं। इसकी जांच तीन न्यायाधीशों की आंतरिक जांच कमेटी कर रही है। मंगलवार को शिकायतकर्ता महिला ने कमेटी की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए आगे उसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय जांच कमेटी में दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे, इंदिरा बनर्जी और इंदू मल्होत्रा शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि शिकायतकर्ता महिला के कमेटी की कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार करने के बाद कमेटी ने इस मामले में एकपक्षीय सुनवाई आगे जारी रखने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में बुधवार को कमेटी ने सीजेआइ रंजन गोगोई को जांच के सिलसिले में कमेटी से मिलने का आग्रह किया था। जिसे स्वीकार करते हुए गोगोई कमेटी के समक्ष पेश हुए।

मंगलवार को शिकायतकर्ता महिला ने कमेटी की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कमेटी ने उसके एक कान से कम सुनाई देने, भयभीत और नर्वस होने के बावजूद उसे वकील या सपोर्ट देने वाला कोई व्यक्ति साथ रखने की इजाजत नहीं दी है। उसके अनुरोध के बावजूद कमेटी की कार्यवाही की आडियो व वीडियो रिकार्डिंग नहीं हो रही है। कमेटी की कार्यवाही के दौरान 26 और 29 तारीख को दर्ज उसके बयानों की प्रति भी उसे मुहैया नहीं कराई गई। न ही उसे कमेटी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया बताई गई। लगता है कि उसे इस कमेटी से न्याय नहीं मिलेगा इसलिए वह आगे से इसकी कार्यवाही में भाग नहीं लेगी।